



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092023-248815  
CG-DL-E-18092023-248815

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945

No. 218]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

जांच शुरूआत

(मध्यावधि समीक्षा)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: एसएसआर (एनसी/01/2023)

विषय: यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित या निर्यातित एसीटोन के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क के संबंध में सिंगापुर के निर्माता/निर्यातक के नाम में बदलाव तक सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत।

फा. सं. 7 /09/2023- डीजीटीआर.— 1. नाम परिवर्तन के लिए एक आवेदन आईएनईओएस फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक विचाराधीन उत्पाद का एक विदेशी उत्पादक/निर्यातक है और कंपनी सिंगापुर गणराज्य के कानून, कंपनी अधिनियम 1967 के तहत सिंगापुर में निगमित है।

2. आवेदक ने अंतिम निष्कर्षों में संशोधन का अनुरोध किया है, जो अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी दिनांक 5 मार्च 2019 के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें यूरोपीय संघ में उत्पादित या निर्यात किए गए "एसीटोन" के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की गई थी। सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके बाद उन्हें "विषय देश" के रूप में भी जाना जाता है), और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 14/2019-सीयूएस (एडीडी), दिनांक 25 मार्च 2019 जिसमें केंद्र सरकार ने निश्चित एंटी-डंपिंग लगाया था विषयगत देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर शुल्क।

**क. पृष्ठभूमि**

3. जबकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, 1995 और उसके बाद संशोधित (इसके बाद अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) को ध्यान में रखते हुए। नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (बाद में इसे नियमों के रूप में भी जाना जाता है), नामित प्राधिकारी (इसके बाद प्राधिकरण के रूप में भी जाना जाता है) ने अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी के माध्यम से अपने अंतिम निष्कर्ष जारी किए थे। दिनांक 5 मार्च 2019 को यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित या निर्यात किए गए "एसीटोन" के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की गई।
4. और जबकि केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 14/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 25 मार्च 2019 के माध्यम से, विषयगत देशों में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया था।

**ख. उत्पाद विचाराधीन**

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "एसीटोन" है जो यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न या निर्यात किया जाता है। आवेदन में विचाराधीन उत्पाद पिछली जांच के समान है, अर्थात्, 5 मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम निष्कर्ष, जिसने पीयूसी को निम्नानुसार परिभाषित किया है-

*"विचाराधीन उत्पाद 'एसीटोन' है। एसीटोन एक कार्बनिक रसायन है जिसे डाइमिथाइल केटोन के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग थोक फार्मास्यूटिकल्स, कृषि रसायन, डाई सामान, कुछ विस्फोटक और डाउनस्ट्रीम रसायनों के निर्माण में किया जाता है। एसीटोन को कस्टम टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत उप-शीर्षक 29141100 के तहत वर्गीकृत किया गया है।*

*यह एकल ग्रेड में उत्पादित एक बुनियादी कार्बनिक रसायन है। यह एक रंगहीन तरल है जिसमें सुखद ईथर जैसी गंध होती है। इसका उपयोग अनेक कार्बनिक संश्लेषणों में या तो विलायक के रूप में या मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग थोक फार्मास्यूटिकल्स, कृषि रसायन, डाईस्टफ, कुछ विस्फोटक और डाउनस्ट्रीम रसायनों के निर्माण में किया जाता है। एसीटोन का उपयोग विशेष रूप से आइसोफोरोन, डायएसीटोन, अल्कोहल, मिथाइल मेथैक्रिलेट और बिशफेनोल ए के निर्माण में किया*

जाता है। इसके अलावा, इसका उपयोग कुछ रबर रसायनों या ऑक्सी एसिथिलीन सेलुलोज़ एसिटेट के निर्माण में किया जाता है।

6. इस जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद अपरिवर्तित है।

ग. **देश शामिल**

7. वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल देश सिंगापुर है (जिसे "विषय देश" भी कहा जाता है)।

घ. **नाम परिवर्तन के लिए आधार**

8. अंतिम निष्कर्षों के साथ-साथ मूल जांच की प्रासंगिक सीमा शुल्क अधिसूचना में, निर्माता मित्सुई फिनोल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (56.91 यूएस डॉलर प्रति एमटी) पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया है।

9. आईएनईओएस फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने एक नाम परिवर्तन आवेदन दायर किया है जिसमें कहा गया है कि आईएनईओएस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा अपने मौजूदा शेयरधारकों से मित्सुई फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप नाम परिवर्तन हुआ है। अपने आवेदन में, आवेदक ने नाम परिवर्तन को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य और दस्तावेज प्रदान किए हैं:

(क) मित्सुई फिनॉल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक का संकल्प, अधिग्रहण को अधिकृत करना और उसके बारे में अधिक विवरण प्रदान करना।

(ख) सिंगापुर के लेखांकन और कॉर्पोरेट नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई कंपनी की अद्यतन व्यावसायिक प्रोफाइल, नाम में परिवर्तन को दर्शाती है।

(ग) सिंगापुर के लेखा और कॉर्पोरेट नियामक प्राधिकरण द्वारा नए नाम के साथ कंपनी के निगमन की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र शामिल है।

(घ) कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य (प्रमुख जोखिम प्रतिष्ठान) विनियम 2017 के अनुसार संयंत्र के पंजीकरण का अद्यतन प्रमाण पत्र।

(ङ) प्रेस विज्ञप्तियाँ जिनमें अधिग्रहण और नाम परिवर्तन का विवरण शामिल है।

10. दावा किया गया है कि किसी नई इकाई का निर्माण नहीं हुआ है। तदनुसार, आईएनईओएस फिनोल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने दावा किया कि उनके निर्यात पर वही शुल्क लगाया जाना चाहिए जो मित्सुई फिनोल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के लिए अनुशंसित और लगाया गया है। आईएनईओएस फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने अंतिम निष्कर्षों और संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचना में शुल्क तालिका में संशोधन के लिए अनुरोध किया है।

ड. **शुरूआत**

11. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और उसके तहत बनाए गए एंटी-डंपिंग नियमों के तहत प्राधिकरण को एंटी-डंपिंग कर्तव्यों को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

12. आईएनईओएस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा मित्सुई फिनॉल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के शेयरों के अधिग्रहण के बाद नाम परिवर्तन के अनुरोध को इंगित करने वाले आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए,

नामित प्राधिकारी अब अधिसूचना संख्या द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों की मध्यावधि समीक्षा करना उचित समझता है। 5 मार्च 2019 की अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी और 25 मार्च 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 14/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत प्रावधानों के अनुसार निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया। सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9ए(5) को एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 23 के साथ पढ़ा जाए। वर्तमान समीक्षा अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 7/26/2018-डीजीएडी दिनांक 5 मार्च 2019 और दिनांक 25 मार्च 2019 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 14/2019 के संबंध में मेसर्स आईएनईओएस फिनोल्स सिंगापुर पीटीई लिमिटेड द्वारा दावा किए गए नाम परिवर्तन के पहलू तक सीमित है।

**च. जांच की अवधि**

13. चूंकि वर्तमान समीक्षा जांच केवल नाम बदलने तक ही सीमित है, इसलिए प्राधिकरण मानता है कि जांच की अवधि उपयुक्त नहीं है।

**छ. प्रक्रिया**

14. वर्तमान जांच के लिए नियमों के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

**ज. सूचना प्रस्तुत करना**

15. सभी संचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) , [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) , [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) पतों पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए।
16. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग से संबंधित जानकारी अलग से दी जा रही है ताकि वे सभी प्रासंगिक जानकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से नीचे दाखिल कर सकें।
17. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से जांच से संबंधित अपने प्रस्तुतीकरण कर सकता है।
18. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्ष को उसका एक गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
19. इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नामित प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित नजर रखें।

**झ. समय सीमा**

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी नामित प्राधिकारी को ईमेल [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in) , [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in) , [jd12-dgtr@gov.in](mailto:jd12-dgtr@gov.in) और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) पतों पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों की मांग करने वाला नोटिस उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा जिस दिन इसे नामित

प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या प्रेषित किया गया था। निर्यातक देश का उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

21. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) बताएं और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

**ज. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

22. कोई भी पक्ष प्राधिकरण के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतिकरण करता है या गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो उसे नियमों के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार नोटिस के संदर्भ में उसी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।

23. प्रश्नावली प्रतिक्रिया सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी सबमिशन (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों सहित) करने वाले पक्षों को, उसके किसी भी भाग पर "गोपनीयता" का दावा किए जाने की स्थिति में, उसे दो अलग-अलग सेटों में दाखिल करना आवश्यक है:

(क) एक सेट को गोपनीय के रूप में चिह्नित किया गया (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि के साथ), और

(ख) अन्य सेट को गैर-गोपनीय के रूप में चिह्नित किया गया है (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि के साथ)

24. "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "गैर-गोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिह्नांकन के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकरण द्वारा गैर-गोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे प्रस्तुतिकरणों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

25. गैर-गोपनीय संस्करण को गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति की आवश्यकता होती है, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त किया जाता है (यदि अनुक्रमणिका संभव नहीं है) और जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसके आधार पर सारांशित किया जाता है। गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के सार को उचित ढंग से समझने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और जिन कारणों से सारांश संभव नहीं है, उनका विवरण प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

26. प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर प्राधिकरण गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि

सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है।

27. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या गोपनीयता दावे पर कोई उचित कारण बताए बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
28. प्राधिकरण संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पार्टी को इसका खुलासा नहीं करेगा।

**ट. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण**

29. नियमों के नियम 6(7) के अनुसार, कोई भी इच्छुक पक्ष अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के गैर-गोपनीय संस्करण वाली सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण कर सकता है।

**ठ. असहयोग**

30. ऐसे मामले में जहां कोई इच्छुक पक्ष उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी तक पहुंचने से इनकार करता है, या अन्यथा प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, प्राधिकरण अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसा उचित समझे।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Department of Commerce )

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**NOTIFICATION**

**INITIATION**

(Mid Term Review)

New Delhi, the 18th September, 2023

**Case No. SSR (NC/01/2023)**

**Subject: Initiation of a midterm review investigation limited to change of name of producer/exporter from Singapore regarding anti-dumping duty imposed on imports of Acetone originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa, and United States of America.**

**F. No.7/09/2023-DGTR.—1.** An application for change of name has been filed by INEOS Phenols Singapore Pte Ltd. (herein after referred to as “applicant”). The applicant is a foreign producer/exporter of the product under consideration and the company is incorporated in Singapore, under the statutes of the Republic of Singapore, Companies Act 1967.

2. The applicant has requested for amendment in the final findings which was issued vide Notification No. 7/26/2018-DGAD dated 5<sup>th</sup> March 2019 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of "Acetone" originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America (hereinafter also referred to as the “subject countries”), and Customs Notification No. 14/2019-Cus (ADD), dated 25 March 2019 wherein the Central Government had imposed definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**A. Background**

3. Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had issued its final findings vide Notification No. No. 7/26/2018-DGAD dated 5 March 2019 recommending definitive anti-dumping duty on the imports of "Acetone" originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America.
4. And whereas the Central Government, vide Customs Notification No. 14/2019-Cus (ADD), dated 25 March 2019, had imposed definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**B. Product under consideration**

5. The product under consideration (PUC) in the present investigation is "Acetone" originating in or exported from European Union, Singapore, South Africa and United States of America. The product under consideration in the application is the same as the previous investigation, i.e., final findings issued vide Notification No. 7/26/2018-DGAD dated 5th March 2019, which defined the PUC as follows-

*"The product under consideration is 'Acetone'. Acetone is organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives, and downstream chemicals. Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29141100.*

*It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic synthesis either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bisphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acetylene Cellulose Acetate."*

6. The product under consideration for this investigation is unchanged.

**C. Country Involved**

7. The country involved in the present review investigation is Singapore (also referred to as the "subject country").

**D. Grounds for Name Change**

8. In the final findings as well as the relevant Customs Notification of the original investigation, the anti-dumping duty has been imposed on the producer Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd (56.91 US\$ per MT).
9. INEOS Phenols Singapore Pte Ltd. has filed a name change application stating that the acquisition of shares of Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd by INEOS Holdings Limited from its existing shareholders has resulted in a name change. In their application, the applicant has provided the following evidence and documents to establish the name change:
  - a. The director's resolution of the Board of Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd, authorizing the acquisition and providing further details thereof.
  - b. The updated business profile of the Company as provided by the Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore, reflecting the change in name.
  - c. The constitution of INEOS Phenols Singapore Pte Ltd., including the certificate confirming incorporation of the company with the new name by the Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore
  - d. Updated certificate of registration of the plant as per the Workplace Safety and Health (Major Hazard Installations) Regulations 2017.
  - e. Press releases containing details of the acquisition and name change.

10. It has been claimed that there has not been any creation of a new entity. Accordingly, INEOS Phenols Singapore Pte Ltd claimed that their exports should be subject to the same duty as recommended and imposed for Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd. INEOS Phenols Singapore Pte Ltd has further requested for amendment in the duty table in the final findings and corresponding customs notification.

**E. Initiation**

11. The Customs Tariff Act, and the Anti-dumping Rules made thereunder, requires the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duties.
12. Having regard to the information provided by the applicant indicating request for name change following acquisition of shares of Mitsui Phenols Singapore Pte Ltd by INEOS Holdings Limited, the Designated Authority now considers it appropriate to conduct a Mid Term Review of the Final Findings notified vide Notification No. vide Notification No. No. 7/26/2018-DGAD dated 5 March 2019 and the definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 14/2019-Cus (ADD), dated 25 March 2019, in terms of the provisions of Section 9A (5) of Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 of the anti-dumping Rules supra. The present review is limited to the aspect of name change claimed by M/s INEOS Phenols Singapore Pte Ltd. with regard to the Final Findings Notification No. 7/26/2018-DGAD dated 5th March 2019 and Customs Notification No. 14/2019-Cus (ADD) dated 25th March 2019.

**F. Period of Investigation**

13. Since the present review investigation is restricted to only change of name, the Authority considers that the period of investigation is not relevant.

**G. Procedure**

14. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed in the present investigation.

**H. Submissions of Information**

15. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [jd12-detr@gov.in](mailto:jd12-detr@gov.in), and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in).
16. The known producers/exporters in the subject country, their government through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to other interested parties.
19. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

**I. Time Limit**

20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg13-dgtr@gov.in](mailto:adg13-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [jd12-detr@gov.in](mailto:jd12-detr@gov.in), and [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti- Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.



21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

**J. Submission of information on confidential basis**

22. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
23. The parties making any submission (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- a. one set marked as confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
  - b. the other set marked as non-confidential (with title, number of pages, index, etc.)
24. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within seven (7) days of receiving the non-confidential version of the application.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**K. Inspection of Public File**

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**L. Non-cooperation**

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority